भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

तटीय कर्नाटक में उन्नत डिजिटल कौशल प्रशिक्षण

2895. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तटीय कर्नाटक में उन्नत डिजिटल कौशल प्रशिक्षण सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कवरेज और सेवा विश्वसनीयता की समीक्षा की है और तटीय कर्नाटक सहित कर्नाटक में कार्यक्रम कवरेज एवं भागीदारी कितनी है;

(ख) आवेदनों, लाभार्थियों, संस्थानों, निधि, कंप्यूट या प्लेटफॉर्म उपयोग और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पहुंच, भाषा, अवसंरचना, अंतरसंक्रियता, कौशल या शिकायत निवारण प्रक्रिया की कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मापन योग्य क्षेत्रीय लक्ष्यों के साथ विस्तार और कार्यान्वयन रोडमैप क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** दिनांक 30.06.2026 तक, देश भर में कुल 5,16,787 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4,07,122 सीएससी ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक में, 15,526 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 11,689 सीएससी शामिल हैं। सीएससी नेटवर्क तटीय जिलों सहित राज्य के सभी जिलों में फैला हुआ है। कर्नाटक सहित देश में सीएससी की जिलावार सूची www.csc.gov.in पर उपलब्ध है।

सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) और कर्नाटक सहित देश भर में अन्य एकीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकारी, वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा और अन्य नागरिक-केंद्रित ई-सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। सीएससी सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य भागीदार संगठनों के सहयोग से विभिन्न शिक्षा और कौशल विकास सेवाओं तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में रोजगार क्षमता में वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षा सहायता, उच्च शिक्षा और अन्य प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण सेवाएं शामिल हैं।

डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी), लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और अन्य एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ लागू हो, सेवा पंजीकरण, शिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन को सुगम बनाते हैं। कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार, सेवाएँ उपयोगकर्ता-शुल्क-आधारित तथा भागीदार समर्थित मॉडलों के तहत ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इंडियाएआई मिशन के तहत, सरकार सीएससी नेटवर्क के माध्यम से लगभग 5.6 लाख ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के लिए मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) के साथ नैसकॉम फ्यूचरस्किल्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के एकीकरण के माध्यम से "युवा एआई फॉर ऑल" कार्यक्रम लागू किया जा रहा है,

जो एआई सीखने की सामग्री तक निर्बाध पहुंच और शिक्षार्थी भागीदारी की निगरानी को सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सहित सीएससी नेटवर्क में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कर्नाटक में सीएससी के माध्यम से किए गए लेनदेन की जिलावार संख्या निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**लेन-देन (लाख में)**
बागलकोट	4.33
बेल्लारी	6.29
बेलगावी	13.30
बेंगलुरु ग्रामीण	1.72
बेंगलुरु शहरी	3.83
बीदर	4.28
चामराजनगर	2.16
चिक्काबल्लापुरा	2.03
चिक्कमंगलूर	2.89
चित्रदुर्ग	4.72
दक्षिणा कन्नड़	4.59
दावनगेरे	5.23
धारवाड़	4.89
गदग	5.22
हसन	3.51
हावेरी	6.09
कलबुर्गी	6.86
कोडगु	0.69
कोलर	2.03
कोप्पल	3.21
मांड्या	3.31
मैसूर	5.17
रायचूर	3.86
रामनगर	2.16
शिवमोग्गा	4.94
तुमकुरु	4.19
यूडीपीआई	2.33
उत्तरा कन्नड़	3.13
विजयपुरा	4.23
विजयनगर	0.23
यादगीर	3.47
कुल	**124.89**

वीएलई के नियमित क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, निगरानी तंत्र, शिकायत निवारण प्रणालियों और केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए

लगातार कदम उठाए जाते हैं। संख्या बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की ई-जिला सेवाओं के एकीकरण के माध्यम से डीएसपी (डीएसपी) पर सेवाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जहां भी संभव हो, सीएससी सेवाएं क्षेत्रीय भाषाओं में पेश की जाती हैं, और डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए सीएससी के पास आवश्यक डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध है। सेवा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उचित सहायता और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं।

नए ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को शामिल करने, नागरिक केंद्रित सेवाओं के विस्तार और निरंतर प्रौद्योगिकी संवर्द्धन के माध्यम से सीएससी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिससे कर्नाटक सहित देश भर में सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ किया जा सके।

सरकार ने कर्नाटक राज्य सहित देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) लागू किया है। इस परियोजना को एक भागीदार एजेंसी के रूप में सीएससी नेटवर्क के साथ लागू किया गया था। देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। कर्नाटक राज्य में, इस योजना के तहत कुल 24+ लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। देश भर में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना का कुल बजट परिव्यय 2351.38 करोड़ रुपये था। यह योजना दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हुई।

सरकार ने 62.58 करोड़ रुपये के बजट के साथ सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से "पायलट प्रोजेक्ट: डिजिटल विलेज का कार्यान्वयन" लागू किया है। परियोजना के घटकों में से एक 'शिक्षा सेवाएं' और 'कौशल विकास' था। यह परियोजना कर्नाटक के 30 गांवों सहित देश भर के 700 गांवों में लागू की गई है। इस परियोजना को 31 मार्च, 2024 से सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है। इन 2 घटकों (यानी 'शिक्षा सेवाएं' और 'कौशल विकास') का विवरण इस प्रकार है:

- शिक्षा सेवाएं: इस परियोजना के तहत प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम- बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी), कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (सीसीसी) पर पाठ्यक्रम, टैली-कौशल प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी में बेसिक कोर्स (बीसीआईटी)।
- कौशल विकास: (क) ऑटोमोटिव तकनीशियन, (ख) हैंडसेट रिपेयर, (ग) फील्ड तकनीशियन – घरेलू उपकरण, (घ) विद्युत तकनीशियन।

शिक्षा सेवाओं और कौशल विकास घटकों के अंतर्गत लाभाथयों की संख्या/लक्ष्यों/उपलब्धियों की संख्या इस प्रकार है -

क्रम सं	**डिलिवरेबल्स**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	नाइलिट - बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी)	45,498
2	नाइलिट - कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (सीसीसी) पर पाठ्यक्रम	10,178
3	टेली- कौशल प्रमाण पत्र	14,000
4	सूचना प्रौद्योगिकी पर बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीआईटी)	40,600
5	ऑटोमोटिव सर्विस तकनीशियन (टू-व्हीलर) (2 प्रति गांव)	1,400
6	हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर (2 प्रति गांव)	1,400
7	फील्ड तकनीशियन – घरेलू उपकरण (2 प्रति गांव)	1,400
8	विद्युत तकनीशियन (2 प्रति गांव)	1,400

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल दक्षता कार्यक्रम संचालित करता है, जिनमें डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कौशल-आधारित दीर्घकालिक/अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। नाइलिट अपने 56 स्वयं के केंद्रों और देशभर में 9,000+ साझेदार संस्थानों के व्यापक नेटवर्क

के माध्यम से, जिनमें चित्रदुर्ग में एक केंद्र तथा कर्नाटक में लगभग 76 सुविधा केंद्र शामिल हैं, कंप्यूटर अवधारणा में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि जैसे डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहुँचाना संभव हो पाता है। इस नेटवर्क के माध्यम से, नाइलिट ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.92 लाख+ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

*****